

Daily Current Affairs in Hindi 22 November 2018

बैंकिंग और वित्त से संबंधित वर्तमान मामले

भारत में 50% एटीएम मार्च 2019 तक बंद हो सकते हैं: सीएटीएमआई रिपोर्ट

- संचालन की अयोग्यता के कारण मार्च 2019 तक लगभग 50 प्रतिशत स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम) बंद हो सकती हैं, शहरी और ग्रामीण आबादी दोनों में कड़ी टक्कर मार रही है, बुधवार को एटीएम उद्योग (सीएटीएमआई) के कन्फेडरेशन ने चेतावनी दी थी।
- सीएटीएमआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारत में लगभग 2,38,000 एटीएम हैं, जिनमें 1,00,000 एटीएम, 1,00,000 ऑफ-साइट और 15,000 से अधिक सफेद लेबल एटीएम शामिल हैं, उनके शास्तर डाउन होने की उम्मीद है।
- उन्होंने कहा कि सीटीएमआई कदम एटीएम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उन्नयन के लिए हालिया नियामक दिशानिर्देशों, नकद प्रबंधन मानकों पर हालिया जनादेश और नकदी लोड करने के कैसेट स्वैप विधि के कारण मजबूर होना पड़ता है।

आरबीआई पूँजी अधिशेष पर मुद्दों को देखने के लिए विशेषज्ञ पैनल स्थापित किया जायेगा

- आरबीआई बोर्ड ने सोमवार को केंद्रीय बैंक के साथ 9.6 9 लाख करोड़ रुपये की अधिशेष पूँजी से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना का फैसला किया और एमएसएमई क्षेत्र में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्गठन के लिए एक योजना पर विचार करने की सलाह दी।
- बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक में, आज शाम मुंबई में निष्कर्ष निकाला गया, यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) को तत्काल सुधार कार्य (पीसीए) ढांचे और आर्थिक के तहत बैंकों के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों की जांच करेगा।
- पूँजीगत ढांचे के मुद्दे पर, आरबीआई अधिशेष भंडार के बारे में अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल तैयार करेगा और क्या उसे सरकार को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय समिति की संरचना का फैसला करेंगे। बोर्ड ने फैसला किया कि कहा समिति भविष्य में देखेगी और पिछले उदाहरणों पर ध्यान नहीं देगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बयान के मुताबिक, बोर्ड ने शीर्ष बैंक को 250 मिलियन तक की कुल क्रेडिट सुविधाओं के साथ छोटे और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं की तनावग्रस्त मानक परिसंपत्तियों के पुनर्गठन के लिए एक योजना पर विचार करने की सलाह दी है, इस तरह की शर्तों के अधीन वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पांच समझौते पर हस्ताक्षर किए

- 22 नवंबर, 2018 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने निवेश को बढ़ावा देने और अक्षम, द्विपक्षीय निवेश, वैज्ञानिक सहयोग और कृषि अनुसंधान और शिक्षा सहित सेवाओं सहित सहयोग बढ़ाने के लिए पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय राष्ट्रपति राम नाथकोविंद और ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच हुई वार्ता के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय राष्ट्रपति ऑस्ट्रेलिया आने के लिए

राज्य का पहला भारतीय प्रमुख बन गया है। वह 21 नवंबर को देश में अपने दो राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में पहुंचे।

निम्नलिखित पांच समझौते हैं:

- विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच समझौता और अलग-अलग सेवाओं को सेवाएं प्रदान करना।
- द्विपक्षीय निवेश की सुविधा के लिए निवेश भारत और ऑस्ट्रेल के बीच समझौता।
- वैज्ञानिक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, कैनबरा में स्थित रांची और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन में आधारित केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान के बीच समझौता।
- कृषि अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, गुंटूर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय, पर्थ के बीच समझौता।
- संयुक्त पीएच.डी. इंट्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली और कॉसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्रिस्बेन के बीच समझौता।

ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मरीज़ पायने और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री अनंतकुमार हेगड़े की मौजूदगी में दोनों देशों के उच्चायुक्तों द्वारा समझौतों का आदान-प्रदान किया गया था।

भारत और वियतनाम ने चार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

- भारत और वियतनाम ने 21 नवंबर, 2018 को वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन फुट्रोंग और भारतीय राष्ट्रपति राम नाथकोविंद के बीच व्यापक बातचीत के बाद 21 नवंबर, 2018 को वियतनाम के बाद की राजकीय यात्रा के दौरान 21 नवंबर, 2018 को संयुक्त वक्तव्य जारी किया।
- राष्ट्रपति कोविंद और वियतनामी राष्ट्रपति गुयेन फुट्रोंग के बीच वार्ता के बाद, दोनों देशों के बीच चार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौतों में शामिल हैं:

- संचार के क्षेत्र में सहयोग पर वियतनाम के सूचना एवं संचार मंत्रालय और भारतीय संचार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन
- वियतनाम के विदेश मामलों और भारतीय व्यापार चैंबर के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन (आईएनसीएचएम)
- हो ची मिन्ह नेशनल एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स, हा नोई, वियतनाम और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत के बीच समझौता ज्ञापन
- भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और वियतनाम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (वीसीसीआई) के बीच सहयोग समझौता

कैबिनेट ने करतरपुर गलियारे परियोजना के विकास को मंजूरी दी

- ऐतिहासिक निर्णय में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतरपुर गलियारे के निर्माण और विकास को मंजूरी दे दी है।

- मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को ब्रीफ करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सभी आधुनिक सुविधाओं और सुविधाओं के साथ करतरपुर गलियारा परियोजना केंद्र सरकार के वित्त पोषण के साथ लागू की जाएगी। यह पूरे वर्ष गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने के लिए तीर्थयात्रियों को एक आसान और आसान मार्ग प्रदान करेगा।
- एक द्वीट में, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान से उनके क्षेत्र में उपयुक्त सुविधाओं के साथ गलियारे का सहारा देने और विकसित करने का आग्रह किया जाएगा। एक और बड़े फैसले में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुल्तानपुर लोढ़ी के ऐतिहासिक शहर को स्मार्ट सिटी सिद्धांतों पर विरासत शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।
- सुल्तानपुर लोढ़ी में विरासत परिसर, गुरु नानक देवजी के समय में जीवन को चित्रित करने के लिए पिंड बाबे नानक दा को विकसित किया जाएगा। सुल्तानपुर लोढ़ी रेलवे स्टेशन को अपग्रेड और विकसित किया जाएगा।

रेल बुनियादी ढांचे आधुनिकीकरण के लिए जिंदल स्टेनलेस ने रेलवे के साथ हाथ मिलाया है

- जिंदल स्टेनलेस रेलवे के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए विशेष रूप से पुल सेगमेंट में रेलवे के साथ हाथ मिलाया है।
- कंपनी, जो सबसे बड़े घरेलू स्टेनलेस स्टील के खिलाड़ियों में से एक है और कोचों में 60% बाजार हिस्सेदारी है, ने इनोरेल इंडिया 2018 के तीसरे संस्करण में रेलवे के आर्म रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) के साथ साझेदारी की है।
- अगले साल मुंबई में भायंदर स्टेशन पर पहला ऐसा स्टेनलेस स्टील फुट-ओवर-ब्रिज आ रहा है।
- अगले 4-5 सालों में, रेलवे सालाना लगभग 10,000 स्टेनलेस स्टील कोच बनाने की योजना बना रही है।
- भारत की 7500 किलोमीटर की तटरेखा स्टेनलेस स्टील के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की आवश्यकता को बढ़ाती है।

सीसीईए जूट सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग के लिए मानदंडों के विस्तार को मंजूरी दी

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जूट पैकेजिंग सामग्री (जेपीएम) अधिनियम, 1987 के तहत अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों के दायरे को विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है।
- सीसीईए ने अनुमोदित किया कि 100 प्रतिशत अनाज और चीनी का 20 प्रतिशत विवादास्पद जूट बैग में अनिवार्य रूप से पैक किया जाएगा। विविध जूट बैग में चीनी पैक करने का निर्णय जूट उद्योग के विविधीकरण को बढ़ावा देगा।
- प्रारंभिक रूप से जेम पोर्टल पर रिवर्स नीलामी के माध्यम से अनाज पैकिंग के लिए जूट बैग के इंडेंट्स का 10 प्रतिशत रखा जाएगा। यह धीरे-धीरे कीमत की खोज के शासन में आ जाएगा।
- निर्णय जूट क्षेत्र के विकास को भर देगा, कच्चे जूट की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि, जूट क्षेत्र के विविधीकरण और जूट उत्पाद की मांग को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए भी।
- इस तथ्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि लगभग 3.7 लाख श्रमिक और कई लाख कृषि परिवार जूट क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए आश्रित हैं।

नेपाल में भारतीय द्रूतावास और सीआईआई मिलकर नेपाल में प्रदर्शनी कॉन्फ्रेंस 2018 आयोजित करेंगे

- नेपाल में भारत के द्रूतावास और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) 22 नवंबर, 2018 से काठमांडू के पास भक्तपुर में निर्माण उपकरण और प्रौद्योगिकी-कॉन्फ्रेंस 2018 की प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं।

- भारत के 150 से अधिक व्यवसाय प्रदर्शकों और कंपनियां 3-दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे।
- 200,000 वर्ग फुट से अधिक प्रदर्शन क्षेत्र के साथ, प्रदर्शनी को नेपाल की निर्माण उपकरण की सबसे बड़ी प्रदर्शनी के रूप में तैयार किया गया है। प्रदर्शनी के दौरान 4000 से अधिक व्यवसायिक आगंतुकों की उम्मीद है।
- नेपाल के भौतिक बुनियादी ढांचे और परिवहन मंत्री रघुबीर महासाथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। नेपाल में भारत के राजदूत, मनजीव सिंह पुरी अतिथि अतिथि होंगे।

गुजरात सरकार ने पानी की कमी प्रभावित किसानों के लिए नए उपायों की घोषणा की

- गुजरात सरकार ने राज्य में पानी की कमी प्रभावित किसानों के लिए नए उपायों की घोषणा की है।
- उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि 12 नवंबर से सरदार सरवर बांध से रबी फसलों को बोने की योजना बनाने वाले किसानों के लिए नर्मदा नहरों में 19, 920 क्यूसेक पानी जारी किया जा रहा है।
- आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार कमजोर इलाकों में अतिरिक्त 7 करोड़ किलोग्राम चारा प्रदान करेगी।

भारत और राज्यों से संबंधित वर्तमान मामले

रिलायंस जियो ने भारत की पहली वोल्ट अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग शुरू की

- रिलायंस जियोइनफोकॉम लिमिटेड (जियो) ने बुधवार को भारत और जापान के बीच वोल्ट-आधारित इनबाउंड अंतरराष्ट्रीय रोमिंग के लॉन्च की घोषणा की।
- इसके साथ, भारत भारत में वोल्ट-आधारित अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला 4 जी मोबाइल ऑपरेटर बन गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय रोमर्स एचडी वॉयस और एलटीई हाई स्पीड डेटा का आनंद लेंगे।
- जापान स्थित केडीडीआई निगम जियो के वोल्ट कॉलिंग और एलटीई डेटा अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा का लाभ उठाने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदाता है, जो अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को जियो के ऑल-आईपी, 4 जी पर उच्च गति डेटा और वॉयस सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने 'इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल' कार्यक्रम शुरू किया

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 21 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इनोवेशन सेल के तहत संस्थान की इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी) कार्यक्रम शुरू किया।
- एचआरडी मंत्रालय ने देश भर में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचआईआई) में अभिनव की संस्कृति को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने के लिए एआईसीटीई में 'इनोवेशन सेल' की स्थापना की है। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि यह नवाचार को संस्थागत बनाने और देश में एक वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- 1000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों (एचआईआई) ने पहले से ही अपने परिसरों में आईआईसी का गठन किया है और एमएचआरडी के इनोवेशन सेल द्वारा प्रबंधित आईआईसी नेटवर्क के लिए नामांकित किया

है ताकि बहुसंख्यक तरीकों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके ताकि उनके परिसरों में एक नवाचार पदोन्नति पर्यावरण प्रणाली हो सके।

- अधिकांश विकसित देशों में, विश्वविद्यालय मुख्य शोध केंद्र हैं और उनके शोध के कारण, राष्ट्रों को वैश्विक नवाचार रैकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त है।

राष्ट्रपति कोविंद ने सिडनी में पररामट्रा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन किया

- 22 नवंबर, 2018 को राष्ट्रपति राम नाथकोविंद ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पररामट्रा में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया।
- इस अवसर पर भारतीय समुदाय का स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय की बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस अवसर पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन भी उपस्थित थे।
- दोनों नेताओं ने भारतीय डायस्पोरा को संबोधित किया और भारतीय राष्ट्रपति ने हिंद स्वराज को ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री को भी प्रस्तुत किया।

मंत्रिमंडल ने सिल्वासा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दादरा और नगर हवेली के संघ शासित प्रदेश (यूटी) में सिल्वासा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
- 150 साल के वार्षिक नामांकन के साथ दो साल, 2018-19 - 114 करोड़ और 2019-20 - 75 करोड़ रुपये में होने वाली 189 करोड़ रुपये की पूँजीगत लागत पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की उम्मीद है।
- परियोजना 2019-20 तक पूरी की जाएगी और निर्माण और पूँजी व्यय भारतीय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) मानदंडों और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बाहरी दिशानिर्देशों के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने छतरी योजना 'एक्रोस' के तहत नौ उप योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दे दी

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 1450 करोड़ रुपये की 2017-2020 लागत के दौरान छतरी योजना "वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाओं (एसीआरएसएस)" की नौ उप-योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दे दी है।
- इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अपने संस्थानों अर्थात् भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), नेशनल सेंटर फॉर मध्यम रेज मौसम पूर्वानुमान (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) और महासागर सूचना सेवा के लिए भारतीय राष्ट्रीय केंद्र के माध्यम से लागू किया जाएगा (आईएनसीओआईएस)।
- सीसीईए ने 2020-21 और उसके बाद के दौरान 130 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ एयरबोर्न रिसर्च (एनएफएआर) के लिए राष्ट्रीय सुविधा की स्थापना को भी मंजूरी दी।
- एक्रोस योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है और मौसम और जलवायु सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है, जिसमें चक्रवात, तूफान की बढ़त, गर्मी की लहरें और आंधी के लिए चेतावनियां शामिल हैं।

नियुक्तियों से संबंधित वर्तमान मामले

उबर ईट्स आलिया भट्ट को अपना पहले ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया

- 22 नवंबर को खाद्य वितरण प्लेटफार्म उबर ईट्स ने भारत में अपने ब्रांड एंबेसडर के रूप में आलिया भट्ट की नियुक्ति की घोषणा की, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर कंपनी का पहला राजदूत बनाया गया।
- उबर ईट्स वर्तमान में भारत के 37 शहरों में स्तरीय शहरों में मजबूत उपस्थिति के साथ मौजूद है। पिछले 3 महीनों में, ऐप पर ऑर्डर की संख्या छह गुना बढ़ी है और उबर ईट्स रोज़ाना अपने मंच पर 100 नए रेस्तरां जोड़ रही है।
- पिछले महीने, उबर ईट्स ने भारत में आभासी रेस्तरां का नेटवर्क विकसित करने के लिए कैफे कॉफी डे के साथ भी करार किया था।

विश्व से संबंधित वर्तमान मामले

अमेरिका, दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास' फॉल ईगल

- संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने 2019 के वसंत के लिए निर्धारित वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, फॉल ईगल को शुरू किया है।
- अमेरिकी रक्षा सचिव जिम मैटिस के अनुसार, यह कदम उत्तरी कोरिया के साथ परमाणु वार्ता की सुविधा है।
- फोयल ईगल सहयोगियों द्वारा आयोजित नियमित संयुक्त अभ्यासों में से सबसे बड़ा है और हमेशा उत्तरी कोरिया को परेशान करता है, जिसने इसे आक्रमण की तैयारी के रूप में निंदा की है।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने 20 साल पूरे किये

- इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) 20 नवंबर, 2018 को 20 साल की उम्र में बदल गया। इस परियोजना को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्कोस ने लात मार दिया था जब उसने 20 नवंबर, 1998 को कज़ाखस्तान में बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से अपना ज़ाराया मॉड्यूल लॉन्च किया था।
- लॉन्च का पीछा नासा के एकता मॉड्यूल द्वारा किया गया था। जोड़ी कम पृथ्वी की कक्षा में शामिल हो गई थी, जिसने मानवता के इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजना के 13 साल के निर्माण प्रयास को शुरू किया। प्रयास का परिणाम एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह था, जो वर्तमान में एक विशाल कक्षीय वैधशाला और प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।
- 20 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अपने पहले मॉड्यूल के लॉन्च के बाद से दो दशक के मील का पथर तक पहुंच गया।
- इस दिन 1998 में, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एयरोस्पेस इंजीनियरों ने रूस-निर्मित, यूएस-वित्त पोषित इकाई ज़ाराया ("सूर्योदय") के लिफ्ट-ऑफ का जश्न मनाया क्योंकि यह कज़ाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से निकला था।

पुरस्कार से संबंधित वर्तमान मामले

नंदिता दास को एफआईएपीएफ पुरस्कार प्राप्त होगा

- फिल्म निर्माता नंदीता दास को 29 नवंबर, 2018 को ब्रिस्बेन में 12 वें एशिया प्रशांत स्क्रीन अवॉर्ड्स (एपीएसए) में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन (एफआईएपीएफ) पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- एशिया प्रशांत क्षेत्र में फिल्म में उनकी उपलब्धि की मान्यता में दास को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- एशिया प्रशांत स्क्रीन पुरस्कार और इसकी अकादमी के अध्यक्ष माइकल हॉकिन्स ने घोषणा की थी।